



2026:AHC:167770-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 14587/2026

श्री ओ.के. सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: कमलेंद्र पाल सिंह, रघुवंश मिश्र
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 49

माननीय न्यायमूर्ति अजय भनोट
माननीय न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र समंत

याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री जी.एस. चतुर्वेदी, विद्वान अधिवक्ता श्री रघुवंश मिश्र के सहयोग से, प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता एक सेवानिवृत्त सरकारी सेवक है। जिस कंपनी ने राज्य सरकार के साथ करार किया था, उसने अपने देय के संदाय में व्यतिक्रम किया। विवादित पत्र राजस्व अभिलेखों में की गई प्रविष्टियों के अनुरूप है, जो याचिकाकर्ता की संक्रमणीय अधिकार सहित भूमिधर के रूप में स्थिति की संपुष्टि करती हैं। याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार को छलने का कोई कार्य कारित नहीं किया। अभिलेख यह प्रकट नहीं करता कि बैंक को याचिकाकर्ता द्वारा निष्पादित दस्तावेज़ के आधार पर ऋण राशि जारी करने हेतु भ्रमित किया गया था। एफ.आई.आर. में अभिकथन मिथ्या हैं। एफ.आई.आर. खारिज किए जाने योग्य है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



श्री अनूप त्रिवेदी, विद्वान अपर महाधिवक्ता, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-। श्री परितोष कुमार मालवीय के सहयोग से, प्रस्तुत करते हैं कि दिनांक 28.06.2011 को हिमवत पावर प्राइवेट लिमिटेड और राज्य सरकार के मध्य एक करार किया गया था। करार ने उक्त कंपनी द्वारा भूमि के स्वत्व और उपयोग पर विभिन्न निर्बंधन अधिरोपित किए। संविदा की सुसंगत शर्त नीचे उद्धृत की जाती है:

"(8) द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग का, विक्रय, बंधक, दान, पट्टे अथवा अन्यथा द्वारा अंतरण नहीं किया जाएगा, सिवाय राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के।"

याचिकाकर्ता एक सरकारी अधिकारी था जिसने दिनांक 07.05.2013 को उक्त शर्त के विरुद्ध कंपनी को एक पत्र जारी किया। उक्त संसूचना में यह अभिलिखित किया गया कि उक्त कंपनी संक्रमणीय अधिकार सहित भूमिधर बन गई।

विद्वान अपर महाधिवक्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता की ओर से उपर्युक्त कृत्य कपट की कोटि में आता है क्योंकि इसने उन तृतीय पक्षों के लिए, जो राज्य और कंपनी के मध्य करार के पक्षकार नहीं थे, विवादित भूमि के स्वामित्व की स्थिति को परिवर्तित कर दिया। स्वामित्व की स्थिति के बारे में बैंकों और अन्य पक्षकारों को भ्रमित करने हेतु कंपनी के अधिकारियों तथा अन्य अभियुक्तगण के साथ याचिकाकर्ता की साठगांठ से संबंधित अन्य पहलू विवेचना के विषय हैं। इसके अतिरिक्त, राजस्व अभिलेख की उन प्रविष्टियों की असलियत, जो विवादित भूमि के टुकड़े पर कंपनी के स्वामित्व को दर्शाती हैं, जो राज्य की ओर से किए गए करार के विरुद्ध हैं, की भी विवेचना की जा रही है।

विद्वान अपर महाधिवक्ता का तर्क है कि एफ.आई.आर. तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री प्रथम-दृष्टया संज्ञेय अपराधों के कारित होने को प्रकट करती है जिसमें गहन विवेचना अपेक्षित है। विवेचना गतिमान है। इस प्रक्रम पर याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से विवेचना में बाधा उत्पन्न होगी, साक्ष्य की क्षति या लोप होगा और यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हरियाणा **राज्य बनाम भजन लाल (1992 सप्प (1) एससीसी 335)** और **निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य (2021) 19 एससीसी 401** में प्रतिपादित विधि के विरुद्ध होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



भजन लाल (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"102. संहिता के अध्याय XIV के अंतर्गत विभिन्न सुसंगत उपबंधों के निर्वचन की पृष्ठभूमि में तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत असाधारण शक्ति अथवा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की एक शृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों की, जिन्हें हमने ऊपर उद्धृत और पुनरुत्पादित किया है, पृष्ठभूमि में, हमने दृष्टांत स्वरूप निम्नलिखित श्रेणियों के वाद दिए हैं जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए अथवा अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, यद्यपि किन्हीं ऐसे यथार्थ, स्पष्ट रूप से परिभाषित तथा पर्याप्त रूप से माध्यमीकृत और अनम्य दिशानिर्देश अथवा दृढ़ सूत्र अधिकथित करना तथा उन असंख्य प्रकार के वादों की, जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, एक संपूर्ण सूची देना संभव न हो।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद में किया गया अभिकथन, यदि उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और पूर्णतः स्वीकार कर लिया जाए, तब भी प्रथम-दृष्टया कोई अपराध गठित नहीं करते अथवा अभियुक्त के विरुद्ध कोई वाद नहीं बनाते।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभिकथन तथा एफ.आई.आर. के साथ संलग्न अन्य सामग्री, यदि कोई हो, कोई संज्ञेय अपराध प्रकट नहीं करते, जो संहिता की धारा 155(2) की परिधि के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के आदेश के अतिरिक्त, संहिता की धारा 156(1) के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों द्वारा विवेचना को न्यायोचित ठहराए।

(3) जहां एफ.आई.आर. या परिवाद में की गई अविवादित अभिकथन तथा उनके समर्थन में एकत्र साक्ष्य, किसी अपराध के कारित होने को प्रकट नहीं करते तथा अभियुक्त के विरुद्ध कोई वाद नहीं बनाते।

(4) जहां एफ.आई.आर. में अभिकथन कोई संज्ञेय अपराध गठित नहीं करते अपितु केवल असंज्ञेय अपराध गठित करते हैं, वहां संहिता की धारा 155(2) के अंतर्गत परिकल्पित मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी पुलिस अधिकारी द्वारा कोई विवेचना अनुज्ञेय नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(5) जहां एफ.आई.आर. या परिवाद में किया गया अभिकथन इतना बेतुका और स्वभावतः असंभाव्य हैं कि जिनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति इस न्यायोचित निष्कर्ष पर कदापि नहीं पहुंच सकता कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु पर्याप्त आधार विद्यमान है।

(6) जहां संहिता के अथवा संबंधित अधिनियम (जिसके अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही संस्थित की गई है) के किन्हीं उपबंधों में कार्यवाहियों के संस्थित किए जाने और चालू रखे जाने पर कोई अभिव्यक्त विधिक वर्जन अंतर्गृथित है, और/अथवा जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में व्यथित पक्षकार की व्यथा के लिए प्रभावकारी निवारण उपबंधित करने वाला कोई विशिष्ट उपबंध विद्यमान है।

(7) जहां कोई आपराधिक कार्यवाही प्रकटतः दुर्भावना से युक्त है और/अथवा जहां कार्यवाही अभियुक्त से प्रतिशोध लेने के अंतरस्थ हेतु से तथा निजी व व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे क्षति पहुंचाने की दृष्टि से द्वेषपूर्ण रूप से संस्थित की गई है।

103. हम इस आशय की एक सावधानी की टिप्पणी भी देते हैं कि किसी आपराधिक कार्यवाही को खारिज करने की शक्ति का प्रयोग अत्यंत विरलता से तथा सतर्कता के साथ और वह भी विरलतम में विरलतम वादों में किया जाना चाहिए; कि न्यायालय एफ.आई.आर. या परिवाद में की गई अभिकथनों की विश्वसनीयता या असलियत अथवा अन्यथा के संबंध में जांच में प्रवृत्त होने में न्यायोचित नहीं होगा तथा असाधारण या अंतर्निहित शक्तियां न्यायालय को अपनी मर्जी या सनक के अनुसार कार्य करने की मनमानी क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करती हैं।"

निहारिका (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय ने विधि को निम्नानुसार प्रतिपादित किया:

"33.16. उपर्युक्त मानदंड प्रयोज्य होंगे और/अथवा उपर्युक्त पहलुओं पर उच्च न्यायालय द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 482 और/अथवा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत शक्तियों के प्रयोग में अभिखंडन याचिका में अंतरिम आदेश पारित करते समय विचार किया जाना अपेक्षित है। तथापि, अभिखंडन याचिका की लंबितता के दौरान विवेचना पर रोक का अंतरिम आदेश सतर्कता के साथ पारित किया जा सकता है। ऐसा अंतरिम आदेश नियमित रूप से, आकस्मिक रूप से और/अथवा यांत्रिक रूप से पारित किए जाने की अपेक्षा नहीं की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जानी चाहिए। सामान्यतः, जब विवेचना प्रगति पर हो और तथ्य अस्पष्ट हों तथा संपूर्ण साक्ष्य/सामग्री उच्च न्यायालय के समक्ष न हो, तो उच्च न्यायालय को गिरफ्तार न करने अथवा “कोई प्रपीड़क कदम न अपनाए जाने” का अंतरिम आदेश पारित करने से स्वयं को विरत रखना चाहिए तथा अभियुक्त को सक्षम न्यायालय के समक्ष दं.प्र.सं. की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत हेतु आवेदन करने के लिए निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय दं.प्र.सं. की धारा 482 और/अथवा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अभिखंडन याचिका को खारिज/निपटाते समय, न तो गिरफ्तार न करने और/अथवा “कोई प्रपीड़क कदम नहीं” का आदेश विवेचना के दौरान अथवा विवेचना पूर्ण होने तक और/अथवा दं.प्र.सं. की धारा 173 के अंतर्गत अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने तक पारित करने के लिए न्यायोचित होगा और न ही तदनुसार है।”

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **भजन लाल** (उपरोक्त) और **निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर** (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय वर्तमान वाद के तथ्यों पर पूर्णतः प्रयोज्य हैं तथा हमें याचिकाकर्ता को कोई अंतरिम संरक्षण प्रदान करने से निरुत्साहित करते हैं।

एफ.आई.आर. के अभिखंडन हेतु मांगा गया अनुतोष भी तदनुसार उन्हीं कारणों से अस्वीकार किया जाता है।

रिट याचिका निरस्त की जाती है।

(न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र समंत) (न्यायमूर्ति अजय भनोट)

11 अगस्त, 2026

ए.डी.वाय.